हरिभूमि
बेमेतरा भूमि
रायपुर, बुधवार 17 जुलाई 2024
बेमेतरा | देवकर | नवागढ़ | साजा | परपोड़ी | थानखम्हरिया | नांदघाट

तापमान
अधिकतम 31.5 डिग्री
न्यूनतम 16.8 डिग्री

12 शासकीय कन्या प्राथमिक शाला देवकर में बाल कैबिनेट का ...

10 निगम सीमा में 469 आंगनबाड़ी भवन विहीन ...

स्थापना वर्ष 2014
आइये मेडिकल के क्षेत्र में अपना भविष्य बनायें ...
विजन पैरामेडिकल
INFORMATION *CAREER GUIDANCE *ADMISSION
* COUNSELING & COACHING CENTER
प्रवेश प्रारंभ
गुणवत्ता युक्त एवं विश्वसनीय सेंटर
सभी पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ में नौकरी एवं रजिस्ट्रेशन हेतु मान्य हैं।
मोबा. 9340751120, 9131330801
गर्ल्स हॉस्टल सुविधा उपलब्ध
पता: रायपुर रोड, शासकीय पी.जी. कॉलेज के सामने, सृजन ITI के पीछे, कोबिया, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
योग्यता - 12 वीं (जीव विज्ञान)
COURSES
BACHELOR IN MED.LAB. TECHNICIAN - 3 Years
DIPLOMA IN MED.LAB. TECHNICIAN - 2 Years
DIPLOMA IN AYURVEDIC PHARMACY - 2 Years
DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN - 2 Years
DIPLOMA IN OPTHELMIC TECHNICIAN - 2 Years
CERTIFICATE IN OT TECHNICIAN - 1 Year

खबर संक्षेप

मोहलाई में गुरूपूर्णिमा पर चौका आरती 21 को

बालोद। सद्गुरू श्री कबीरघाट धर्मानुरागी समित द्वारा गुरूपूर्णिमा महोत्सव एवं सात्विक यज्ञ चौका आरती का आयोजन 21 जुलाई को कबीरघाट मोहलाई में सुबह 10 बजे से किया गया है।
कार्यक्रम में महात्मा लेखचंद साहेब अपनी संत मंडली सहित ज्योतिकुंज मुरमुंदा से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू होंगे, अध्यक्षता विधायक गुण्डरदेही कुंवरसिंह निषाद करेंगे। विशेष अतिथि पूर्व विधायक बीरेन्द्र साहू, अध्यक्ष तहसील साहू संघ अर्जुन्दा उमाशंकर साहू, सदस्य जिला पंचायत बालोद नीतीश मोंटी गवालेंद्र, सरपंच ग्राम पंचायत कोंगनी डेमिन जितेन्द्र साहू, उपसरपंच ग्राम पंचायत कोंगनी चुनुलाल साहू, सरपंच ग्राम पंचायत कुरदी संजय कुमार साहू, सरपंच ग्राम पंचायत धनगांव उत्तम निषाद उपस्थित रहेंगे।

निलंबित आरक्षक नौकरी से बर्खास्त

भिलाई। निलंबित आरक्षक सहदेव सिंह यादव को अपराधिक आचरण, अनुशासनहीनता समेत अन्य कारणों से एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने बर्खास्तगी की कार्रवाई की है। 11 जुलाई को सहदेव को सोमनी राजनांदगांव से गिरफ्तार हुआ था। सहदेव सिंह यादव के खिलाफ धारा 420, 467,468, 471, 120 बी 34, 7,11 समेत अन्य धाराओं के तहत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों ने कार्रवाई किया। सहदेव पर मनीलाड्रिंग का आरोप है। गौरतलब हो कि ऑनलाइन सट्टा महादेव बुक को लेकर सहदेव पर गंभीर आरोप भी लगे है। इसके अलावा भीम यादव, अजुर्न यादव की इससे पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके खातों से करोड़ों रुपए का लेनदेन होना बताया जा रहा है।

बैंक कर्मियों ने मिलकर लोन खाते से की ठगी

भिलाई। इलाहाबाद बैंक के कर्मियों द्वारा लोन के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने धारा 385,409,420,467,468,471,120 बी ,34 के तहत जुर्म दर्ज किया है। मोहन नगर पुलिस ने बताया कि वार्ड 19 कैलाश नगर निवासी तिजिल सिंह गणेश सिंह, निखिल सिंह ने शिकायत किया है कि लोन खाते में ईलाहाबाद बैंक के कर्मियों द्वारा जालसाजी कर ठगी किया है। बैंक कर्मियों में एल आर ठाकुर, रिमी घोष, अजय शिंडे, बीपी सिंह, कमल सिदार्थ, आनंद सुलेमान, राजेश बेलसरे, अतीश श्रीवास्तव,अरुण सिंह का नाम सामने आया है। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इलाहाबाद बैंक संतराबाडी दुर्ग में स्थित है। जिसे इंडियन बैंक के रूप में मर्ज कर संचालित किया जा रहा है। तिजिल सिंह से 21 लाख 50 हजार, गणेश सिंह से 52 लाख 82 हजार 500 और निखिल सिंह से 28 लाख रुपए की ठगी बैंक कर्मियों द्वारा किया गया है।

बीएसपी के पूर्व डीजीएम की कमरे में मिली लाश

भिलाई। बीएसपी के पूर्व डीजीएम की बेडरुम में संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने का मामला सामने आया है। सूचना पर मौके पर पहुची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। स्मृति नगर पुलिस ने बताया कि बीएसपी के मैत्रीबाग के चौहान टाउन जुनवानी निवासी पूर्व प्रभारी डीजीएम तजविंदर सिंह क्षत्रिय का शव उनके मकान के कमरे में मिला है।

रायपुर और बेमेतरा मार्ग पर लिमाही व कर्मा चौक बेरला डिवाइडर क्षतिग्रस्त

नगर में दो स्थानों पर टूटा डिवाइडर गहराने लगी दुर्घटना की आशंका

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बेरला

ब्लॉक मुख्यालय बेरला में बनाए गए डिवाइडर अलग-अलग जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। लिहाजा बेरला ब्लॉक अपने आप में एक शहर के साथ नगरीय निकाय है।

जहां से एक तरफ रायपुर और दूसरी तरफ बेमेतरा रोड की ओर डिवाइडर युक्त दो लाइन सड़क का निर्माण हुआ है। उक्त लोगों को आने-जाने में कोई प्रकार की समस्या न हो। आपको बता दें कि बेरला मुख्यालय के लिमाही चौक पर अज्ञात वाहन द्वारा इन डिवाइडर को टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लगभग 15 से 20 फिट तक टूट जाने के बाद भी मरम्मत के नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं, कर्मा चौंक बेरला में यही स्थिति बनी हुई है। जिससे लोग बेधड़क आवागमन कर रहे हैं। रायपुर से बेमेतरा की ओर जाने वाले मार्ग बेरला में डिवाइडर युक्त सड़क बने हुए है। जहां पर कई स्थानों पर डिवाइडर की अमानक आने जाने व टूटे हुए हैं। यह स्थिति लोक निर्माण विभाग के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी गयी है। जिसकी वजह से यह हादसों को न्योता दे रहा है। इसके बावजूद अधिकारी मौन हैं।

जेब्रा ब्रेकर की मांग

दोपहिया व चार पहिया वाहन इसके बीच से निकाले जा रहे हैं। इसके कारण दूसरी तरफ से आ रहे तेज रफ्तार वाहन टकरा जाते हैं और लोग घायल हो जाते हैं। वहीं, तेज गति से वाहन चलाने के कारण भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। लिहाजा बेमेतरा जिला में कई सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई जानें भी दशकों में चली गयी हैं। लोगों की मांग है कि जेब्रा ब्रेकर होने पर लोग जरूर रुकते हैं। अपनी गाड़ियों की रफ्तार नियंत्रित करते हैं, जिससे हादसे होने की कम संभावना होती है।

पटवारियों की हड़ताल 9वें दिन भी जारी, लोगों को हो रही परेशानी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बेमेतरा

■ पेंशनर्स संघ ने भी आंदोलन को दिया समर्थन

ऑनलाइन भुंईया में गंभीर समस्याओं के निराकरण नहीं होने एवं 1 वेतन विसंगति, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, संसाधन एवं भत्ते, अतिरिक्त हल्के का भत्ता 50 प्रतिशत, पटवारी भर्ती की योग्यता स्नातक किया जाने से लेकर मुख्यालय बाध्यता समाप्त होने व बिना विभागीय जाँच प्राथमिकी नही किए जाने सहित सारंगढ़ मे निलंबित पटवारी उमेश कुमार पटेल को बहाल किया किए जाने की मांग को लेकर पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल 8 जुलाई से जारी है जिसे मंगलवार को पेंशनर्स संघ ने अपना समर्थन दिया। गौरतलब हो कि पटवारी संघ का अनिश्चित कालीन हड़ताल लगातार 9वां दिन भी जारी रहा । जिला मुख्यालय स्थित जय स्तम्भ चौक तहसील कार्यालय के पास आंदोलन पर बैठे पटवारियों के चलते राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण योजना के साथ सरकार की राजस्व पखवाडा भी प्रभावित हो रहा है ।

आंदोलन के समर्थन में शामिल छतीसगढ़ पेशनर समाज के प्रमुख पदाधिकारी रोमन लाल जायसवाल, पी.आर. सिन्हा, मोती धन गोश्वामी, व्यासनारायण पाण्डेय, गोरे सिंह राजपूत, कुंजीलाल दुबे, आर. एस. यदु, एन. पी. साहू, एम. जी प्रकाश राव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे और पटवारियों को मांगो को सरकार जल्द से जल्द पूर्ण करने की मांग दोहराई । इस दौरान पटवारी संघ जिलाध्यक्ष बोधी राम निषाद ने पेशनर संघ पदाधिकारीयों का आभार एवं धन्यवाद प्रेषित किया। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से पटवारी अभिषेक माली, विजय पाल,शैलेन्द्र जायसवाल, महेंद्र साहू, परस साहू, कुमार गौरव साहू, सनत मंडावी, ऋषि निर्मलकर, अनिल क्षत्रिय, जानकी कुर्रे,कमलेश चेलक, चंद्रप्रकाश साहू, मेघराज पटेल, साकेत, सेन कुमार घोष, राजकुमार,दिनेश नामदेव, लोकेश ध्रुव, मुकेश साहू,ओंकार सोनवानी, भोमलता, अम्बा उपाध्याय, भारत ठाकुर, ओंकार राजपूत, संजय ध्रुव, मेघनाथ वर्मा,युवराज साहू, कविता भारती, राजन साहू, नवरतन साहू, सुरेखा सोनी, श्वेता मिश्रा, रेखा दिवान, भोमलता , चंद्रकांता, ज्योति तिवारी, देवेंद्र राजपूत , चंद्रप्रकाश साहू, अंकित गुप्ता, सुंदरलाल घृतलहरे, युवराज, टूकेश्वर भारती मौजूद रहे।

सड़कों पर उतरी जिला व पुलिस प्रशासन की टीम

एसपी के निर्देश के बाद सड़कों से हटाए जा रहे मवेशी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बेमेतरा

प्रदेश की सड़कों पर आवारा मवेशियों के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीर मसला माना है । जिले में भी नेशनल हाइवे में आवारा मवेशियों का झुंड बना रहता है । एसपी रामकृष्ण साहू ने बीते दिनों सड़क पर उतर कर मवेशियों को हटाने पुलिस महकमे के साथ अभियान शुरू कर दिया था। इस अभियान में जिला प्रशासन भी जुट गया।

कलेक्टर रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन में दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने का अभियान चलाया है । इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर आवारा पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात को सुचारु बनाना था। इस दौरान प्रशासन द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया जो सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने और सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम कर रही हैं । पशुओं को पकड़ने और स्थानांतरित करने के दौरान उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा हैं । अभियान के लिए प्रशिक्षित कर्मियों और विशेष वाहनों का उपयोग किया जा रहा हैं । इस अभियान से सड़कों पर यातायात जाम और दुर्घटनाओं की संभावना में कमी होगा , जिससे यात्रियों की यात्रा सुगम हो सकेंगी। यातायात सुचारु होने से नागरिकों को आने-जाने में आसानी होगी। सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आयेगी ।

सुरक्षित होगी यात्रा

प्रशासन का कहना है कि सड़कों पर आवारा पशुओं के चलते दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही थी। यातायात जाम और वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस अभियान का उद्देश्य न केवल यातायात को सुगम बनाना है, बल्कि शहर की सड़कों को सुरक्षित और साफ-सुथरा रखना भी है। इससे न केवल यात्रियों की यात्रा सुरक्षित होगी, बल्कि शहर का सौंदर्य और स्वच्छता भी बढ़ेगी।

ग्रामीण अंचल में बिना डिग्री इलाज करने वालों की भरमार

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बेरला/कोदवा

■ प्रशासन की उदासीनता से झोलाछाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद

बेरला विकासखण्ड अंतर्गत अंचल के अधिकांश गाँवों में बिना डिग्री के लगातार अवैध चिकित्सकीय गतिविधियां संचालित होने की बात सामने आ रही हैं। इसके बावजूद प्रशासन की उदासीनता से बगैर डिग्रीधारी चिकित्सकों के हौसले बुलन्द हैं। आलम यह है कि गाँवों में भोले-भाले ग्रामीणों को अपने घरों में निजी दवाखाना खोलकर इलाज के नाम पर गैरकानूनी ढंग से उपचार कर पैसा वसूला जा रहा है। इससे आमजन ठगी का शिकार हो रहे हैं।

सूत्रों की माने तो गाँव-गाँव मे बगैर डिग्रीधारी चिकित्सकों का अपना दबदबा एवं प्रभाव कायम है, जिसके कारण आमलोग त्वरित एवं सस्ते इलाज के चक्कर में अवैध रूप से उपचार करने वाले डॉक्टरों के झांसे में आ जाते हैं। लिहाजा डिग्रीधारी चिकित्सकों सहित प्रशासन को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। वहीं, ग्रामीण शासन-प्रशासन की चिकित्सकीय योजनाओं से लाभान्वित भी नहीं हो पा रहे हैं। वैसे तो इस सम्बंध में विगत पूर्व में ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमे एसडीएम को अध्यक्ष एवं बीएमओ व थाना प्रभारी को समिति में लेकर एसडीएम के दिशानिर्देश पर कार्यवाही करने की बात कही जाती है। किन्तु आज भी इस दिशा में कोई खास प्रयास या पहल नहीं हो पाई है।

सुई लगाने से लेकर ड्रीप भी चढ़ा रहे

लिहाजा स्थिति यह है, कि बिना डिग्री के डॉक्टर घरो में अवैध क्लीनिक लगाकर सामान्य उपचार के आड़ में सुई व ड्रीप भी लगाने के साथ स्वयं दवाई एवं मेडिसिन भी बांटकर ग्रामीणों को चूना लगा रहे है। जबकि पूरे क्षेत्र में यह कारोबार व्यापक स्तर पर हो रहा है फिर भी प्रशासन की उदासीनता आमजनता पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इस विषय पर विकासखंड चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क किया गया, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे सरकार

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बेमेतरा

■ गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

पदोन्नति में आरक्षण सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बेमेतरा को ज्ञापन सौंपा। संगठन के बेमेतरा जिला अध्यक्ष खेमसिंह बारले ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञापन में परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण सहित सात सूत्रीय मांगों आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने,पुरानी पेंशन लाभ 30 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने,बस्तर व सरगुजा संभाग के स्थानीय भर्ती में आरक्षण को बहाल करने,फर्जी जाति प्रमाण के माध्यम से नौकरी हासिल करने वालों पर समयबद्ध जांच कर कार्यवाही करने के साथ साथ स्थानांतरण से प्रभावित शिक्षक एल बी संवर्ग के वरिष्ठता के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन के पश्चात ही पदोन्नति किया जाए इसके अलावा बैकलाग के पदों पर शीघ्र भर्ती कराया जाए ओर पदोन्नति से वंचित शिक्षक संवर्ग को मध्यप्रदेश के तर्ज पर प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करने से संबंधी मांग की गई है ।

श्री बारले ने बताया कि संघ अपने चरणबद्ध आंदोलन से पहले प्रथम चरण में प्रदेश के सभी 146 तहसील मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपा है। जिलाध्यक्ष खेमसिंह बारले ने आगे बताया कि बेमेतरा जिला के साजा, नवागढ़ में भी संगठन के ब्लाक ईकाई के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया है।ज्ञापन सौंपने वालों में खेमसिंह बारले,चेतन चतुर्वेदी, जितेन्द्र बघेल प्रशांत माथुर, मूलचंद बंजारे,बसंत घोष, राजकुमार कुर्रे, बाबूलाल गोयल, राकेश ध्रुव व अन्य लोग शामिल रहे।

सफाई के अभाव में बढ़ रही गंदगी, बढ़ा खतरा

विद्यालय व महाविद्यालय परिसर में उगी घास व झाड़ियां

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बेरला/कोदवा

विद्यालय एवं नवीन शासकीय महाविद्यालय देवरबीजा परिसर में सफाई के अभाव के कारण गाजर घास व झाड़ियां उग गई हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्षो पहले ब्लॉक बेरला के ग्राम पंचायत देवरबीजा समीप पंडित देवी प्रसाद चौबे शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय संचालित था।

अब यहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय व नवीन शासकीय महाविद्यालय देवरबीजा संचालित है। मिली जानकारी के अनुसार 16 अगस्त 2023 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे ने देवरबीजा में नवीन शासकीय महाविद्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया गया था। यहां पढ़ाई 2023-24 को शुरू हो गई थी। विद्यालय व महाविद्यालय एक स्थान पर संचालित होने के बाद भी सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

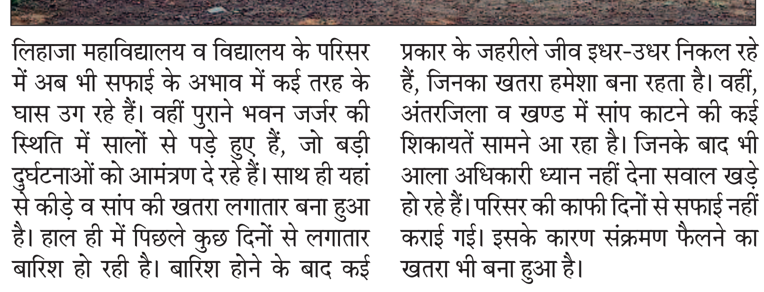

लिहाजा महाविद्यालय व विद्यालय के परिसर में अब भी सफाई के अभाव में कई तरह के घास उग रहे हैं। वहीं पुराने भवन जर्जर की स्थिति में सालों से पड़े हुए हैं, जो बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही यहां से कीड़े व सांप की खतरा लगातार बना हुआ है। हाल ही में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद कई प्रकार के जहरीले जीव इधर-उधर निकल रहे हैं, जिनका खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं, अंतरजिला व खण्ड में सांप काटने की कई शिकायतें सामने आ रहा है। जिनके बाद भी आला अधिकारी ध्यान नहीं देना सवाल खड़े हो रहे हैं। परिसर की काफी दिनों से सफाई नहीं कराई गई। इसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है।

मिडिल स्कूल भवन में हो रहा कॉलेज का संचालन

इस संबंध में नवीन महाविद्यालय देवरबीजा प्राचार्य आईपी दिनकर ने बताया कि महाविद्यालय की भवन व्यवस्था के रूप में चल रहे हैं। ये विद्यालय पूर्व माध्यमिक शाला का है। पूर्व माध्यमिक शाला देवरबीजा प्रभारी प्रधान पाठक उत्तम साहू ने बताया कि शाला परिसर में नाली का पानी घुस जाता है, जिसके कारण गंदगी हो रही है और घास उग रही। उन्होंने कहा कि शाला परिसर की सफाई करते हैं, जबकि महाविद्यालय के आला अधिकारी अपनी ओर सफाई नहीं करते जिससे उनके कार्यालय की तरफ घास उग गई है। इस समस्या को लेकर देवरबीजा सरपंच सुनीता देवांगन से इसकी सफाई को लेकर बात हुई है।

हरिभूमि
पाठक सूचना
बेमेतरा जिले में हरिभूमि समाचार पत्र के स्थान पर कोई अन्य अखबार मिल रहा हो। एवं समाचार पत्र की प्रतियां, विज्ञापन एवं खबरों के लिए संपर्क करें
8319154342, 8224868411

छत्तीसगढ़ से खेलेंगे मुंबई के स्टार क्रिकेट खिलाड़ी भूपेन लालवानी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने सोमवार को रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे समेत सैयद मुश्ताक टी-20 ट्रॉफी के लिए मेंस सीनियर खिलाड़ियों की सूची जारी की है, जिसमें मुंबई से सलामी बल्लेबाज भूपेन लालवानी का नाम शामिल है। भूपेन के आने से अब छत्तीसगढ़ की टीम और भी मजबूत हो सकती है। बता दें कि 2023-24 सीजन के रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाया था। अब आगे घरेलू सीजन में छत्तीसगढ़ के लिए खेलने का फैसला किया है, क्योंकि वह घरेलू क्रिकेट में सफेद गेंद के खेल खेलना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक लालवानी ने इस संबंध में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, एमसीए को अनापत्ति प्रमाणपत्र, एनओसी के लिए आवेदन किया था। संघ के 36 खिलाड़ियों की सूची में शशांक सिंह, अमनदीप खरे, अजय मंडल समेत प्रदेश के खिलाड़ी शामिल हैं।

खास खबर

पिछले सीजन में रणजी ट्रॉफी में बनाए थे सर्वाधिक रन

- छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने 36 सीनियर खिलाड़ियों की सूची की जारी

10 मैच में 5 अर्धशतक और 1 शतक

शानदार प्रदर्शन करते हुए लालवानी ने पिछले सीज़न में मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में 10 मैचों में 39.20 औसत से 588 रन बनाए, जिसमें पांच अर्धशतक और एक शतक शामिल था। अभी तक 14 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने एक शतक और पांच अर्धशतकों के साथ 681 रन औसत 34.05 रन बनाए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वनडे या टी 20 क्रिकेट में पदार्पण नहीं किया है।

सफेद गेंद से आईपीएल की तैयारी

आईपीएल में खेलने के लिए भूपेन छत्तीसगढ़ टीम से घरेलू क्रिकेट में सफेद गेंद से खेलना चाहते हैं। उनका कहना है कि बेहतर अवसरों के लिए मुंबई छोड़ रहा हूं, मैं सभी प्रारूपों में घरेलू क्रिकेट खेलना चाहता हूं, जो मुझे छत्तीसगढ़ के लिए मिलेगा। लालवानी के साथ छत्तीसगढ़ के ड्रेसिंग रूम में अब तीसरे मुंबई के खिलाड़ी होंगे। आईपीएल-2024 में पंजाब किंग्स के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले शशांक सिंह और विकेटकीपर-बल्लेबाज एकनाथ केरकर जिन्होंने 2022 के घरेलू सीजन में मुंबई के सलामी बल्लेबाज अखिल हेरवाडकर भी छत्तीसगढ़ के लिए खेले थे, जबकि मुंबई के पूर्व विकेटकीपर सुलक्षण कुलकर्णी 2016-17 सीजन में मध्य भारत की टीम के मुख्य कोच थे। पांडिचेरी चले गए ऑलराउंडर अमन खान के बाद लालवानी दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस सीजन में मुंबई छोड़ी है।

शहरी क्षेत्र में मनरेगा लागू नहीं होने से फंड के अभाव में अटक रहा निर्माण

निगम सीमा में 469 आंगनबाड़ी भवन विहीन हर महीने 12 लाख से ज्यादा किराया भी दे रहे

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

स्मार्ट सिटी में जहां कई हाईटेक सुविधा लोगों को मिल रही है, वहीं वार्डों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए चलाए जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों में 469 का संचालन किराए के भवनों में किया जाता है। शहर में जगह और फंड के अभाव में विभाग को किराए के भवनों में संचालित केंद्रों का हर महीने 12 लाख से ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में मनरेगा लागू नहीं होने व सिर्फ 30 प्रतिशत बजट ही विभाग को सरकार से मिलता है। इससे किराए के भवनों से आंगनबाड़ी केन्द्रों को मुक्ति नहीं मिली।

अलग खबर

जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के भवनों की स्थिति जांचने पर नई बात सामने आई। इसमें पता चला कि रायपुर जिले में 1882 आंगनबाड़ी एवं मिनी केंद्र हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्र में ही 1410 केंद्रों का संचालन विभाग द्वारा बनवाए गए भवनों में किया जाता है। ग्रामीण बेल्ट में सिर्फ 3 केंद्र ही ऐसे हैं, जिनके लिए भवन नहीं बना है। इस मामले में शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ियों की स्थिति ज्यादा खराब है। वजह जांचने पर पता चला कि शहरी क्षेत्र यानी निगम सीमा में मनरेगा के तहत काम कराने की गाइडलाइन नहीं है। इसके कारण भवन बनाने पर होने वाले कुल खर्च 12 लाख 50 हजार का 70 फीसदी फंड मनरेगा व 30 प्रतिशत राज्य शासन से मिलता है। अभी राज्य शासन से फंड मिलने के बाद भी भवनों का निर्माण अटका है।

- ग्रामीण बेल्ट में सिर्फ 3 केंद्र ही ऐसे हैं, जिनके लिए भवन नहीं बना

अभी शहरी क्षेत्र के लिए स्वीकृति नहीं

समय-समय पर शहरी क्षेत्र में भी आंगनबाड़ी बनाने के लिए फंड मिलता है। निगम सीमा में मनरेगा लागू नहीं होने की वजह से भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है। शहरी क्षेत्र में केन्द्र बनाने स्वीकृति भी नहीं मिली। नियम के मुताबिक किराए की तय राशि केंद्रों को दी जाती है।

- निशा मिश्रा, डीपीओ, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर

किराए के भवनों में जगह भी कम

शहर की सीमा में गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था किराए के भवनों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को करनी पड़ रही है। विभाग से किराया कम मिलने से एक कमरे और छोटे बरामदे के रूप में मिलने वाली जगह में ही बैठाना पड़ता है। बच्चों को खेलने की सुविधा भी किराए के भवनों में खुले आंगबाड़ी केंद्रों में नहीं मिलती। ऐसे भवनों में केंद्र होने से गोद भराई व अन्नप्राशन का आयोजन निगम के भवनों के भरोसे होता है। सीमित जगह होने से आंगनबाड़ी केन्द्र में मिलने वाली सुविधा भी प्रभावित है।

नहीं मिल रहा मनरेगा का 8.75 लाख

एक आंगनबाड़ी भवन बनाने का खर्च 12.50 लाख रुपए आता है। इसमें 8 लाख 75 हजार रुपए मनरेगा से होने वाले काम के बदले ग्रामीण क्षेत्र को मिल जाते हैं। इससे ग्रामीण इलाके में 1410 आंगबाड़ी भवन विभाग ने बनवा लिया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति शहरी क्षेत्र यानी निगम सीमा में आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की है। यहां मनरेगा के तहत काम कराने का नियम नहीं है। इससे 469 केंद्रों का भवन अभी तक नहीं बना है। इसका खामियाजा विभाग को हर महीने किराया भुगतान करना पड़ रहा है। सुविधा भी गाइडलाइन के अनुरूप नहीं मिलती।

स्वीमिंग पूल में एनआईटी के छात्र की डूबने से मौत

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

- मौके पर उपस्थित एम्स के चिकित्सक ने छात्र को डूबते देख स्वीमिंग पूल से बाहर निकलवाया
- घटना सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में पांच दिन पूर्व की, छात्र की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत

सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में पांच दिन पूर्व स्वीमिंग सीखने गए एनआईटी सेकेंड ईयर के छात्र की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना 11 जुलाई शाम 4 बजे के करीब हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच करने तथा छात्र के पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक खमतराई में रहने वाले कारोबारी का पुत्र बताया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, स्वीमिंग पुल में डूबने से कोंडरी आयुष की मौत हुई है। घटना दिनांक को कोंडरी आयुष सेकेंड शिफ्ट में स्वीमिंग सीखने के लिए गया था। स्वीमिंग पूल में एम्स अस्पताल का एक डॉक्टर भी आया हुआ था।

बताया जा रहा है, कोंडरी आयुष तैरते हुए काफी दूर निकल गया। वापस लौटने के दौरान वह डूबने लगा। इसी दौरान मौके पर उपस्थित डॉक्टर ने छात्र को स्वीमिंग पूल में डूबते हुए देख उपस्थित सुरक्षाकर्मियों को छात्र को स्वीमिंग पूल से बाहर निकालने के लिए कहा।

पेट से पानी निकालने के बाद भी नहीं बची जान

पुलिस के अनुसार, कोंडरी आयुष को स्वीमिंग पूल से बाहर निकालने के बाद डॉक्टर ने छात्र के पेट दबाकर पानी निकालने की कोशिश की तो छात्र ने उल्टी की। इसके बाद छात्र को गंभीर स्थिति में उपचार के लिए एम्स अस्पताल ले जाया गया। पांच घंटे के उपचार के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। छात्र के लंग्स में काफी मात्रा में पानी जमा होने की वजह से मौत होने की बात सामने आई है।

खबर संक्षेप

राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों सहित प्रांताध्यक्ष अनिल सिन्हा ने राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देने की मांग स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से की है। इस मौके पर संघ के प्रांताध्यक्ष श्री सिन्हा ने बताया कि लिमिटेड वेतन पर गुजर-बसर कर रहे कर्मचारी पर वज्रपात हो जाता है, जब परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है। ज्ञात हो कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा दिवस के अवसर पर 1 जुलाई से अपने कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य योजना का तोहफा दिया है। इसी तरह राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर से कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालयों में प्रति तीन माह के अंतराल में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि बीमारियों का समय पूर्व निदान हो सके। मांग करने वालों में संघ के तीरथराम साहू, जीआर चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, डॉ. विद्यावती चंद्राकर, मनीष दीपक साहू, योगेश्वर साहू, श्रवण सिन्हा, बीआर साहू, गोविंद राम साहू, गोपेश्वर वर्मा आदि शामिल थे।

बाइक से रेस लगाने के विवाद पर मारपीट

रायपुर। धरसींवा थाने में एक युवक ने दूसरे युवक के खिलाफ बाइक से रेस लगाने के विवाद पर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक, आर्यन बंजारे ने गोलू उर्फ गंगाधर ध्रुव के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। आर्यन ने पुलिस को बताया कि वह सिलयारी में रविवार को अपने दोस्त के साथ खड़ा था। इसी दौरान गोलू नशे की हालत में उसके पास पहुंचा और बाइक से रेस लगाने के लिए कहा। आर्यन द्वारा रेस लगाने की बात से इनकार करने पर गोलू ने आर्यन के साथ मारपीट की।

दिनदहाड़े फायरिंग, कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत एक कारोबारी के कार्यालय के बाहर दिनदहाड़े फायरिंग की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक समय राजधानी रायपुर को शांत शहर के नाम पर जाना जाता था और छत्तीसगढ़ को शांति के टापू के नाम से जाना जाता था, लेकिन राज्य गठन होने के बाद विगत दो दशक से रायपुर अशांत हो गया है। रायपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, गोलीकांड और फायरिंग जैसी गंभीर घटनाएं सामने आ रही हैं, जो की बहुत ही दुख और चिंता का विषय है।

नीलिमा को पीएचडी

रायपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने नीलिमा सिन्हा को मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एवं मेटेरियल साइंस विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। उनके शोध का विषय थ्योरीटीकल डेवलपमेंट ऑफ नोवल पोरस मटेरियल विथ दियर एप्लिकेशन इन सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी रहा। उन्होंने अपना शोध कार्य डॉ. पखोरा एवं डॉ. धीरेंद्र राय के नेतृत्व में पूर्ण किया। डॉ. नीलिमा के नाम पर 10 से अधिक एससीआई-स्कोपस अनुसंधान प्रकाशित हैं। वर्तमान में वे आईआईटी मुंबई में शोधरत हैं। वे भाठागांव निवासी भूपेश कुमार सिन्हा एवं शकुंतला सिन्हा की सुपुत्री हैं।

तेलीबांधा मुक्तिधाम में किया पौधारोपण

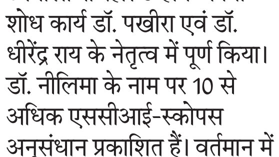

रायपुर। सिंधी साहिती बिरादरी मंडल द्वारा तेलीबांधा मुक्तिधाम में पौधारोपण किया गया, जिसमें 45 पौधें लगाए गए। पौधारोपण करने वालों में मंडल के अध्यक्ष दिलीप इसरानी, महासचिव सुनील अजवानी के साथ ऋतुराज पेशवानी, नरेश लालवानी, हरीश अजवानी, शंकर लाल दानवानी, राजेश विधानी, अनिल हिमानी एवं गोविंद खेमानी उपस्थित रहे।

मामूली विवाद पर चाकू से जानलेवा हमला, आठ गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

- घटना आमानाका थाना क्षेत्र की
- बोर चालू करने के विवाद पर जानलेवा हमला

आमानाका थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने आठ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बोर चालू करने की बात को लेकर गाली-गलौज करने से रोकने पर बदमाशों ने लांड्री कर्मचारी पर लाठी, डंडे, चाकू तथा नारियल काटने वाले औजार से जानलेवा हमला कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, खेमचंद चौधरी की शिकायत पर ऋषभ नेताम, सूरज नेताम, विशाल जगत, संजय सोनी, आदित्य नाग, यशवंत सोनी, जय सोनी, रमाकांत यदु को गिरफ्तार किया है। खेमचंद ने पुलिस को बताया कि वह रविवार को अपने साथियों के साथ डूमर तालाब अटल आवास स्थित लांड्री वर्कशॉप के पास बैठा था। अटल आवास के पास बैठे बदमाशों ने खेमचंद को बोर चालू करने के लिए कहा। बोर चालू करने में देर होने पर बदमाश खेमचंद के साथ गाली-गलौज करते हुए वर्कशॉप के शटर को लात से पीटने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसके शरीर के अलग-अलग भाग में चाकू तथा नारियल काटने वाले औजार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने तलाश कर गिरफ्तार किया।

33 जिलों के लिए माह जुलाई का 552 किलोलीटर केरोसिन आवंटित

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

प्रदेश के 33 जिलों के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 552 किलोलीटर केरोसिन उचित मूल्य दुकानों के लिए आबंटन जारी किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह जुलाई 2024 के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशनकार्डों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसिन प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों एवं हॉकर्स के लिए उचित मूल्य दुकानवार ऑनलाइन आवंटन जारी किया गया है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारी हितग्राहियों को केरोसिन की पात्रता होगी। इसी प्रकार समस्त नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों के लिए अधिकतम एक लीटर केरोसिन की पात्रता होगी और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम 2 लीटर केरोसिन की पात्रता होगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं और उचित मूल्य दुकान के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को केरोसिन का वितरण कराने के लिए कहा है।

मंत्री बघेल ने कहा- खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

- खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने ली समीक्षा बैठक

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सोमवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के सभा कक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर खाद्य विभाग के सचिव बसवराजू एस. विशेष सचिव केडी कुंजाम और खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि विभाग का दायित्व एवं प्राथमिकता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है और समय पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन उपलब्ध कराना है। दूरस्थ क्षेत्रों में चना, गुड़, शक्कर, राशन आदि की आपूर्ति समय पर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं के आपूर्ति, भण्डारण एवं वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद्य मंत्री ने चावल के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के सख्त निर्देश दिए हैं और उचित मूल्य दुकानों आंगनबाड़ी, स्कूल, छात्रावास में गुणवत्ता युक्त चावल भण्डारण एवं वितरण करने के लिए कहा है।

समीक्षा बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लक्ष्य के विरुद्ध चावल उपार्जन की स्थिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण करने के संबंध में चर्चा कह गई। शक्कर, नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को वर्षा ऋतु से पूर्व अग्रिम भण्डारण सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई।

नए कानून बीएनएस के तहत जिले में पहली ऑनलाइन एफआईआर दर्ज

ये है मामला

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने वाली रचना मिश्रा के मुताबिक, वर्ष 2022 में उसे एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर आरोपी दामोदर प्रधान और मनीषा वर्मा ने सवा दो लाख रुपए ठग लिए थे। प्रार्थिया ने आरोपियों को रकम भाठागांव बस स्टैंड में दी थी।

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

देश में नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद राजधानी रायपुर में पहली ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो गई। टिकरापारा थाने में सरायपाली निवासी महिला ने नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की ऑनलाइन तरीके से शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार नौकरी लगाने का झांसा देकर दो लोगों ने उससे सवा दो लाख रुपए ठग लिए।

महिला ने अपनी शिकायत सरायपाली थाने में जीरो में दर्ज कराई है। वहां से यह एफआईआर टिकरापारा थाने को मिली है। इसके बाद अब टिकरापारा पुलिस ने इसमें नंबरी कायम कर प्रकरण को विवेचना में ले लिया है। हालांकि प्रार्थिया को तीन दिन के भीतर थाने आकर इस एफआईआर पर हस्ताक्षर करने होंगे।

सरायपाली पुलिस ने शून्य में ठगी का अपराध दर्ज किया

ये है नए कानून में शून्य में अपराध दर्ज कराने का प्रावधान

- नए कानून में जीरो एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान शुरू किया गया है। अब किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी और एफआईआर को 15 दिन के अंदर घटनास्थल वाले थाने में ट्रांसफर किया जाएगा। पहले घटनास्थल वाले थाने में ही एफआईआर दर्ज कराई जाती थी।
- कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी जीरो एफआईआर दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा, अगर जीरो एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है, जिसमें तीन से सात साल तक सजा का प्रावधान है तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करानी होगी।
- फरियादी को एफआईआर और बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है।

कर रहे जांच

जिले में पहली ऑनलाइन एफआईआर का मामला टिकरापारा थाने में दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी के मामले में सरायपाली थाने से शिकायत मिली है। जांच की जा रही है।

- संतोष कुमार सिंह, एसएसपी रायपुर

ऑनलाइन एफआईआर मिली

सरायपाली थाने से ऑनलाइन एफआईआर प्राप्त हुई। इस मामले में नंबरी कायम कर प्रकरण पर कारवाई शुरू कर दी गई है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 420,34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

- मनोज कुमार साहू, टीआई, टिकरापारा थाना

पार्किंग ठेकेदार पर रेलवे ने लगाया 5 हजार का फाइन, सिस्टम कब सुधरेगा पता नहीं

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

रेलवे पार्किंग में अवैध पर्ची का खेल, जीएसटी नंबर से लेकर गाड़ी नंबर तक, सब गायब के शीर्षक से 14 जून के अंक में हरिभूमि ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद सोमवार को रेलवे प्रशासन ने पार्किंग ठेकेदार पर 5 हजार का फाइन लगाया है। साथ ही पिक एंड ड्रॉप को नियमानुसार संचालित करने का भी निर्देश दिया है।

बता दें कि पार्किंग कर्मचारी लोगों को एक सादे कागज पर ठप्पा लगाकर पैसा वसूल थे, जिसमें गाड़ी नंबर और जीएसटी का जिक्र भी नहीं था। खबर प्रकाशित होने के बाद रेलवे ने जांच के बाद फाइन लगाते हुए पार्किंग ठेकेदार पर कार्रवाई की है, लेकिन लोगों को अब से पार्किंग की वैध पर्ची मिलेगी और सिस्टम का सुधरेगा, इसकी जानकारी भी मंडल के असफर खुद नहीं दे पा रहे हैं। कम्प्यूटराइज्ड पर्ची नहीं देने के पीछे का कारण वाईफाई में दिक्कत बताया जा रहा है। पार्किंग ठेकेदार ने इसकी जानकारी रेलवे को दी है, लेकिन महीनेभर से वाईफाई की दिक्कत ठीक नहीं हुई है। रेलवे प्रशासन ने भी सिस्टम को बेहतर करने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है।

फाइन लगाया गया है

पार्किंग ठेकेदार पर अवैध पर्ची को लेकर फाइन लगाया गया है। इससे अधिक जानकारी नहीं दे पाऊंगा।

- अवधेश कुमार त्रिवेदी, सीनियर डीसीएम, रायपुर मंडल

खबर संक्षेप

100 मिलियन पार, मोदी का परिवार। 'वसुधैव कुटुम्बकम्'

रायपुर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उनके एक्स हैंडल पर फॉलोवर्स की संख्या 100 मिलियन हो गयी है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे अधिक फॉलोवर्स वाले राजनेताओं में से एक हैं। उनकी दुनियाभर में लोकप्रियता अद्वितीय है। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स होने पर अपने एक्स हैंडल पर लिखा '100 मिलियन पार, मोदी का परिवार 'वसुधैव कुटुम्बकम''। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं।

आवासीय विद्यालय मामले में कांग्रेस ने बनाई जांच समिति

रायपुर। पखांजूर इलाके के आवासीय छात्रावास में नाबालिग छात्रा के गर्भवती होने के मामले में कांग्रेस ने 6 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। जांच कमेटी की संयोजक पूर्व मंत्री अनिला भेंड़िया बनाई गई हैं। जांच कमेटी में विधायक अंबिका मरकाम, संगीता सिंह, सावित्री मंडावी, नारायणपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामबती नेताम और कांकेर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा सलाम को शामिल किया गया है। जांच समिति की सदस्य प्रभावित छात्रावास का दौरा कर पीड़िता/परिजनों, छात्रावास प्रशासन तथा ग्रामवासियों से भेंट व चर्चा कर घटना की वस्तुस्थिति से अवगत होकर अपना प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रस्तुत करेगी।

कांग्रेस ने बनाई नगरीय निकाय परिसीमन के लिए समिति

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में हो रहे परिसीमन को लेकर अपनी समिति का गठन किया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की अनुशंसा पर शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने परिसीमन समिति के सदस्यों की नियुक्ति की है। शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जी श्रीनिवास ने जारी सूची में पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, किरणमई नायक, प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर, पंकज शर्मा, ज्ञानेश शर्मा, महेंद्र छाबड़ा, गिरीश दुबे, श्रीकुमार मेनन, कन्हैया अग्रवाल, शिव सिंह ठाकुर, सहित शहर कांग्रेस कमेटी के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल के जिला अध्यक्ष समिति में पदेन सदस्य होंगे।

उत्तर विधायक ने सुनी जनता की समस्या

रायपुर। उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपने प्रतिदिन के वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अंतर्गत महात्मा गांधी (पंडरी) वार्ड के गंगानगर में लोगों की समस्याओं को सुना। गे समलेश्वरी नगर उत्कल बस्ती में जाते वक्त बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश के बीच ही मोहल्ले में बैठकर सभी से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। भारत सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) और प्रदेश के चार नगरीय निकायों बिलासपुर, रायगढ़, चांपा एवं भाटापारा का चयन प्रतिष्ठित 'स्पार्क-2023-24' पुरस्कारों के लिए किया गया है। राज्य में शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं।

दिल्ली में सूडा और चार नगरीय निकाय 18 को होंगे पुरस्कृत

इस बेहतर काम के लिए मिल रहा है पुरस्कार

सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कार शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से नगरीय निकायों ने शहरी आबादी के जीवन में उल्लेखनीय सुधार किया है।

आजीविका AAJEEVIKA NRLM

18 को मिलेगा पुरस्कार

केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटॉट सेंटर में आयोजित समारोह में सूडा और चारों नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यमंत्री तोखन साहू ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।

डिप्टी सीएम साव ने दी बधाई

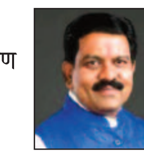

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य को गौरवान्वित करने वाली इस उपलब्धि के लिए सूडा और चारों नगरीय निकायों की टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ये पुरस्कार राज्य के लिए सम्मान का विषय है। मैं इसके लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने भी सूडा और पुरस्कार के लिए चयनित नगरीय निकायों को बधाई दी है।

समिति ने की पहली बैठक, तय किए गए जांच के बिंदु

राशन घोटाले की जांच समिति ने खाद्य विभाग से मांगा कांग्रेस शासनकाल का ब्योरा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

कांग्रेस शासनकाल में हुए 600 करोड़ रुपए के राशन सामग्री बचत घोटाले की जांच समिति की पहली औपचारिक बैठक समिति के सभापति, पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नू लाल मोहिले की अध्यक्षता में हुई। समिति के सदस्यों और विधानसभा के सचिव की उपस्थिति में हुई बैठक में घोटाले की जांच बिंदुओं के संबंध में चर्चा हुई। समिति ने राशन घोटाले को लेकर कांग्रेस शासन काल में राशन सामग्री के वितरण का ब्योरा खाद्य विभाग से मांगा है। विभाग की जानकारी आने के बाद समिति मामले में पूछताछ कर इसके लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय करेगी। बताया जाता है कि समिति के सभापति पुन्नू लाल मोहिले पूर्व भाजपा शासन में खाद्य मंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में पारदर्शी वितरण प्रणाली बनाई गई थी। इसमें दो महीने का पूरा कोटा दिए जाने के बाद तीसरे महीने बीते दो माह का कोटा घटा कर देने का नियम था।

कांग्रेस शासन काल में खाद्य संचालनालय के अपर संचालक ने राशन दुकानों काा कोटा काटने का काम बंद करवा दिया। इसके कारण सिर्फ चार साल में 600 करोड़ का राशन बचत घोटाला हो गया। मामले में जांच का आश्वासन देने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर नई सरकार बनने के बाद विधानसभा के बजट सत्र में सदन में आश्वासन के बावजूद जानकारी न देने पर अवमानना का मामला बताए जाने पर घोटाले की जांच के लिए पांच सदस्यों की सदन की जांच समिति को मामला सौंपा गया। समिति की पहली बैठक में जांच के बिंदु तय किए गए। इसमें कितने राशन दुकानों में राशन सामग्री की कमी पाई गई, कोटा वितरण के समय निरीक्षक माड्यूल से कोटा नहीं घटाने का आदेश किसके द्वारा जारी किया गया।

5 हजार दुकानों में मिली थी गड़बड़ी

प्रदेश की तेरह हजार राशन दुकानों में से पांच हजार राशन दुकान ऐसी हैं, जिनमें 600 करोड़ का राशन गायब है। घोटाले के लिए संचालनालय खाद्य के अधिकारी को जिम्मेदार माना जा है। संचालनालय के सूत्रों के अनुसार खाद्य विभाग के निरीक्षकों से हर महीने घोषणापत्र इंस्पेक्टर माड्यूल में भरवाया गया है। इसके बाद संचालनालय की जिम्मेदारी थी कि कोटा घटा कर दिया जाए। चार साल तक इसका पालन नहीं किया गया। इसके लिए जिम्मेदार खाद्य संचालनालय का अपर संचालक है। केंद्रीय जांच दल दिल्ली को दी गई जानकारी में खाद्य संचालनालय ने स्वीकार किया था कि घोटाला बहुत ज्यादा है और कार्रवाई की जा रही है। तब से घोटाले को दबाने का प्रयास हो रहा था, विधानसभा की जांच समिति में इसका खुलासा होगा।

घोटाले पर पर्दा डालने का खेल

खाद्य संचालनालय के अधिकारी ने विभाग की साइट से तेरह हजार राशन दुकानों का घोषणापत्र हटा दिया। शासन के नियमानुसार राशन घोटाले के लिए जिम्मेदार राशन दुकानों के प्रकरण बनाकर राजस्व वसूली किया जाना चाहिए था, लेकिन बिना प्रकरण बनाए दुकानों से शपथपत्र लेकर घोटाले को दबाया जा रहा है। घोटाले को दबाने के लिए भौतिक सत्यापन का खेल खेला जा रहा है। खाद्य संचालनालय के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पिछले तीन साल में हर साल भौतिक सत्यापन कराए जाने पर राशन दुकानों में कितनी राशन सामग्री पाई गई और कितनी सामग्री काटी गई। तकनीकी त्रुटि बताकर भी घोटाले को दबाया जा रहा है, केवल 996 राशन दुकानों में तकनीकी त्रुटि है, जबकि घोटाला पांच हजार से अधिक राशन दुकानों में है।

जनदर्शन में मजदूर पिता की गुहार

कलेक्टर ने दिए बच्चे को तुरंत हॉस्टल में दाखिला दिलाने के निर्देश

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

कलेक्टर जनदर्शन में एक मजदूरी करने वाले मजबूर पिता ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर अपने बच्चे को हॉस्टल में दाखिला दिलाने के लिए गुहार लगाई। कलेक्टर ने मजबूर पिता के परिवार की स्थिति जानने के बाद अधिकारियों को बच्चे को तुरंत हास्टल में दाखिला कराने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

समता कॉलोनी के राखी नगर निवासी भारत साहू अपने पुत्र गौतम जो छठवीं कक्षा का छात्र है, को हॉस्टल में दाखिल कराना चाहता था। भारत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है तथा उनकी पत्नी व बच्चे की मां झमिता साहू गृहणी है। भारत ने बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और बच्चे को पढ़ाने में भी असमर्थ हूं, जिसके कारण गौतम को आगे पढ़ाने में काफी दिक्कते हो रही थी। इस वजह से वह बेटे को हॉस्टल में दाखिला दिलाने के लिए

कलेक्टर से गुहार लगाई। कलेक्टर ने गंभीरता से उनके आवेदनों का निराकरण करने के लिए आदिम जाति विभाग को निर्देशित किया। इसके तुरंत बाद बच्चे को हॉस्टल में दाखिला दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बच्चे को जल्द ही कुशालपुर के हॉस्टल में दाखिला दिलाया जाएगा। वहां बच्चे को ठहरने, भोजन और अन्य सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा जरूरी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। कलेक्टर गौरव सिंह ने सोमवार को कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक ली। इसमें उन्होंने अधिक से अधिक कृषकों को बीमा आवरण में शामिल करने के लिए निर्देशित किया, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से फसल प्रभावित होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके।

पंजीयन 31 जुलाई तक

जिले में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2024 मौसम के लिए जिले के लिए धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन (ग्राम स्तर पर) फसलों को अधिसूचित फसलों में शामिल किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 जुलाई तक पंजीयन कराना होगा।

नुकसान की भरपाई के लिए बीमा जरूरी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो, शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए बीमा कराना चाहते हैं, वे नियत तिथि के पूर्व अपना फसल बीमा करा सकते हैं। इसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। किसान बैंक अथवा चॉइस सेंटरों के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। प्रति हेक्टेयर बीमित राशि तय : खरीफ फसलों में धान सिंचित के लिए राशि 60 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित के लिए 45 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 42 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर एवं सोयाबीन के लिए 40 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित है।

विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना भी ऑनलाइन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में मानसून सत्र से ध्यानाकर्षण सूचना सदस्यों से प्राप्त करने एवं विभागों द्वारा पत्राचार करने के लिए ऑनलाइन प्रकिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से ऑनलाइन ध्यानाकर्षण प्राप्त करने तथा उसका जवाब देने की चरणबद्ध सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशिक्षण विधानसभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया गया।

विधानसभा सचिवालय में 11 जुलाई को राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विधायकों के लिए ऑनलाइन ध्यानाकर्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, प्रशिक्षण कार्यक्रम में लखेश्वर बघेल, नीलकंण्ठ टेकाम, व्यास कश्यप, प्रबोध मिंज, द्वारिकाधीश यादव एवं रायमुनि भगत सहित अन्य विधायकों

के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुये। साथ ही वर्चुअल माध्यम से भी सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुये। सत्र में ऑनलाइन प्रक्रिया प्रायोगिक रूप से की जा रही है। विधायकों एवं विभागों को ऑनलाइन के साथ ही पूर्वानुसार ऑफलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी। शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऑनलाइन ध्यानाकर्षण की सूचना से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी देने के उद्देश्य से राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र एवं संसदीय कार्य विभाग के सहयोग से मंत्रालय में भी समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

नगरीय निकायों में 27 से 10 अगस्त तक लगेंगे शिविर, मौके पर ही समस्याओं का निपटारा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। पखवाड़ा के दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर स्थानीय समस्याओं का निदान किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है।

184 निकायों में लगेंगे शिविर

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर आयोजित कर उनका मौके पर ही निराकरण के निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिए हैं। उन्होंने इन शिविरो में नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि आमजन की भागीदारी में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि वार्डवार शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा और नागरिकों को जरुरी सुविधाएं मिलेंगी।

सरकार ने जारी किया परिपत्र

उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश के बाद सोमवार को राज्य शासन द्वारा सभी नगरीय निकायों को आगामी 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि स्थानीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्र के नागरिकों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्य दायित्व है। स्थानीय नागरिक समस्याएं यथा नल कलेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण तथा कई विविध छोटे-छोटे कार्य होते हैं, जिनका निराकरण शीघ्र अपेक्षित होता है।

मौके पर ही होगा निराकरण

विभाग ने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं का निराकरण यथासंभव मौके पर ही करना करने के निर्देश दिए हैं। शिविरों में करदाताओं को करों के भुगतान की सुविधा वार्ड में ही उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने वार्डवार शिविरों के आयोजन के संबंध में वार्ड एवं नगर में व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिक शिविर का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। शिविरों में संकलित जानकारियां राज्य शासन को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर जिले में हैं 6 लाख 5 हजार 828 कार्डधारक

5 लाख से अधिक बन चुके नए राशनकार्ड, इनमें 75 हजार एपीएल धारकों का नवीनीकरण नहीं, इसलिए अटके

हरिभूमि न्यूजः रायपुर

रायपुर जिले में 6 लाख 5 हजार 828 कार्ड धारक हैं। इनमें करीब 5 लाख से अधिक नये राशनकार्ड बन चुके हैं, वहीं शेष करीब एक लाखकार्ड अब तक बन नहीं पाए हैं। इनमें ज्यादातर कार्ड एपीएल (सामान्य परिवार) के हैं। नया राशन कार्ड बनाने के लिए पहले केवाइसी और फिर नवीनीकरण अनिवार्य है, लेकिन जिले में 75 हजार एपीएल कार्ड धारकों ने अब तक नवीनीकरण नहीं कराया है, जबकि इनमें करीब 25 हजार कार्ड धारक ऐसे हैं, जो प्रत्येक माह राशन दुकान से खाद्यान्न उठाते आ रहे हैं। इधर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अगस्त माहांत तक नवीनीकरण कराने का समय निर्धारित किया गया है। इस तारीख के बाद भी अगर कोई नवीनीकरण नहीं कराता है, तो उसका कार्ड स्वयमेव निरस्त हो जाएगा। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद से राज्य में राशन कार्ड बदलने की प्रक्रिया चल रही है। राज्यभर में नये राशन कार्ड की छपाई से लेकर नवीनीकरण कराने का काम शुरू कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले तक राज्यभर में 70-75 प्रतिशत नवीनीकरण कराने का काम पूर्ण हो चुका है, वहीं चुनाव के बाद यह आंकड़ा 90 प्रतिशत तक पहुंच गया है। रायपुर जिले में भी करीब 86 प्रतिशत नवीनीकरण का काम पूर्ण हो चुका है।

सितंबर से नया राशनकार्ड अनिवार्य

विभागीय अधिकारियों के अनुसार नया राशनकार्ड बनाने के लिए नवीनीकरण कराने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। इस दौरान नया और पुराना दोनों कार्ड से राशन दुकानों में खाद्यान्न वितरण किए जाएंगे, लेकिन सितंबर से सिर्फ नये कार्ड पर ही खाद्यान्न दिया जाएगा। इसीलिए अगस्त खत्म होने के पहले तक बचे हुए कार्ड धारकों को नवीनीकरण कराना होगा।

परेशानी से बचना है तो कराना होगा नवीनीकरण

"नये राशनकार्ड बनाने के लिए नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। जिन धारकों का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उनके ही अब तक नये कार्ड बन नहीं पाए हैं। नवीनीकरण के लिए अगस्त तक का समय दिया गया है। सितंबर माह से नये कार्ड से ही राशन मिलेगा। परेशानी से बचना है, तो समय सीमा के भीतर कराना होगा नवीनीकरण।

\- भूपेंद्र मिश्रा
जिला खाद्य नियंत्रक रायपुर

अग्रसेन प्रा. आई.टी.आई
ITI DAGANIA
Affiliated By : N.C.V.T & D.G.E.T.
New Delhi (Govt. of India)
भारतीय सेना में कार्यरत/ भूतपूर्व सैनिकों के परिवार एवं दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए संपूर्ण फीस में 25 % की छूट
REGISTRATION OPEN
• ELECTRICIAN 2 Year (10th Pass)
• C.O.P.A. (Computer) 1 Year (10th Pass)
अग्रसेन एजुकेशन केम्पस, ग्राम -डगनिया, दुर्ग-बलोद मेन रोड, तह. गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)
89595-93937 • 89595-44444

खबर संक्षेप

चिंगरी में धूमधाम से मना माता शीतला जुड़वास

अंडा। ग्राम चिंगरी में आषाढ़ माह में धूमधाम से मां शीतला का जुड़वास मनाया गया। गांव के बैगा सालिक राम निर्मलकर ने बताया कि माता शीतला का जुड़वास मनाने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इसका पालन करते हुए 15 जुलाई को सुबह कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद शाम को माता शीतला की विशेष पूजा कर प्रसाद वितरण किया गया। शाम को विभिन्न मंडलियों ने माता जस सेवा गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर गांव के बैगा सालिक राम निर्मलकर, चेतन यादव (बघधर्रा), महेंद्र पटेल, सोमन निर्मल कर, देवान सिंह देशमुख, राजेश्वर देशमुख, चुम्मन देशमुख, राज यादव, राकेश ढीमर, गोपी ढीमर, मणीकांत पटेल, संतराम निर्मलकर सहित सभी ग्रामीण उपस्थित थे।

ओबीसी महासभा के बालोद जिलाध्यक्ष बने संतोष

बालोद। भारतीय जनता पार्टी के नेता बालोद निवासी संतोष कौशिक को ओबीसी महासभा के उत्थान व कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू ने बालोद जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। विदित हो कि ओबीसी महासभा राष्ट्रीय स्तर की पंजीकृत संस्था है। राष्ट्रीय स्तर के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में संगठन मजबूती के साथ ओबीसी समाज के हित में कार्य कर रही है, इनके नियुक्ति से बालोद जिले में संगठन मजबूत होगा।

सड़क हादसे में मौत

भिलाई। अंजोरा चौकी अंतर्गत सोमवार की सुबह रसमड़ा बाइपास के पास बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिरने युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। अंजोरा पुलिस ने बताया कि काली बाड़ी डोगरगढ़ निवासी विश्वजीत पंडा बाइक से दुर्ग आ रहा था। तभी रसमड़ा बाइपास के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होने से दूर जा गिरा। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में विश्वजीत की मौत हो गई।

पीएससी के पूर्व सचिव के मकान में सीबीआई की दबिश

भिलाई। सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई की एक टीम ने भिलाई में दबिश देने पहुची। जहां कई दस्तावेज मिलने की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक टीम ने पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव के सेक्टर 10 स्थित मकान में पहुंची हुई है। सीबीआई के आधा दर्जन अधिकारी जीवन किशोर के मकान में दस्तावेजों की जांच चल रही है। सीबीआई की टीम को देख आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बना रहा है। राज्य सरकार के अनुरोध पर सीबीआई की टीम 2020-2022 की परीक्षा की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व सचिव के यहां दबिश के दौरान कई दस्तावेज मिलने की खबर है। जिसे टीम जांच 2021 की परीक्षा में अनियमितता होने की शिकायत के बाद बीजेपी सरकार ने इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया था। बीते एक महीने से केस में गोपनीय जांच कर रहे अफसरों ने सोमवार 15 जुलाई को जांच करने की आधिकारिक पुष्टि की है। आरोप है कि सीजी पीएससी में अपने चहेतों को नियम कायदों को दर किनार कर भर्ती कराया गया था।

शासकीय एकलव्य कालेज में प्रवेश 25 तक

डौंडीलोहारा। शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौण्डीलोहारा में स्नातक प्रथम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए प्रथम एवं द्वितीय प्रवेश मेरिट सूची जारी की गई थी। उपरोक्त सूची के तहत प्रवेश के बाद रिक्त सीटों पर महाविद्यालय स्तर पर मुक्त प्रवेश के लिए 16 से 25 जुलाई तक प्रवेश दिया जाना है। संस्था के प्राचार्य राजू लाल कोसरे ने बताया कि निर्धारित तिथि में प्रवेश के इच्छुक ऐसे छात्र-छात्राएं, जिन्होंने इस महाविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फार्म भरा है, और जिनका मेरिट सूची में नाम नहीं आया है, वे प्रवेश ले सकते हैं।

जनदर्शन : कलेक्टर शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं

कलेक्टर जनदर्शन में मिले 30 आवेदन

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बेमेतरा

- अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक के बाद कलेक्टोरेट के दृष्टि सभा कक्ष में जनदर्शन का आयोजन किया गया। जनदर्शन में जिले के अलग-अलग क्षेत्र के लोग अपनी-अपनी मांग, समस्याएं एवं शिकायतें लेकर आये। इस दौरान जनदर्शन में आने वाले सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया गया। जनदर्शन में कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को गौर से सुना और संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर और समक्ष बुलाकर संबंधित आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। कुछ आवेदन मौके पर ही निराकरण किए गए। आज जनदर्शन में विभिन्न शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित 30 आवेदन प्राप्त हुए। तात्कालिक महत्व की समस्याओं का जहां त्वरित निराकरण किया। वहीं गंभीर और जांच के आवेदनों को टीएल पंजी पर दर्ज करके, इनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अफसरों को दी।

इस दौरान जनदर्शन में दूरदराज के गांवों से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे लोगों में से तहसील बेमेतरा के ग्राम खैरझिटी के समस्त ग्रामवासी ने सचिव को स्थानांतरण करने के संबंध में आवेदन दिया। बेमेतरा तहसील के ग्राम आदू के समस्त ग्रामवासी ने सरपंच द्वारा पद का दुरूपयोग करकर अनेको विकास कार्यो में पैसा गबन और परिवार के करीबी लोग के पैसे का लेन देन के संबध में आवेदन दिया। थानखम्हरिया तहसील ग्राम पदमी के निवासी टीकाराम गोंड़ ने कृषि भूमि मुआवजा राशि प्रदान किए जाने के संबंध में आवेदन दिया। ग्राम सोमई खुर्द के निवासी रोहितलाल साहू ने शीतला गली का नाली निर्माण कराने के संबंध में आवेदन दिया। तहसील नवागढ़ ग्राम पौसरी के समस्त ग्रामवासी ने शिक्षक को स्थानांतरण करने के संबंध में आवेदन दिया।

अनुकंपा नियुक्ति व पेंशन के लिए आवेदन

तहसील नवागढ़ के ग्राम नांदघाट निवासी मनीष सेवर ने अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय करने के संबंध में आवेदन दियाया। इसके अलावा आम नागरिकों ने निराश्रित पेंशन दिलाने, बैटरी चलित ट्रायसायकल हेतु, प्रधानमंत्री आवास दिलाने, कटा हुआ रकबा जोड़ने, खाद गड्ढा को हटाये जाने, आम रास्ता खुलवाने, वृद्धापेंशन हेतु, दिव्यांगता पेंशन दिलाये जाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए है। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, संयुक्त कलेक्टर अंकिता गर्ग सहित विभिन्न विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

छात्र सुरक्षा बीमा योजना के तहत परिजनों को दी गई बीमा राशि

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बेमेतरा

- कलेक्टर ने किया चेक का वितरण

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने मंगलवार को छात्र सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत जिले अंतर्गत आकस्मिक निधन हुए कुल 29 छात्र छात्राओं के संबंधित परिजनों को एक-एक लाख रुपए का बीमा राशि का चेक प्रदान किया।

इस अवसर पर कलेक्टर ने संबंधित परिवारजनों को सांत्वना दी एवं योजना के महत्व और इसके लाभों को बताया और परिजनों को यह आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। छात्र सुरक्षा बीमा योजना का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, अगर किसी छात्र की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसके परिवार को बीमा राशि प्रदान की जाती है। इस बीमा योजना का लाभ स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मिलता है, जिससे उनके परिवार आर्थिक संकट से उबर सकें। यह योजना छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जो अप्रत्याशित घटनाओं में मददगार साबित होती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, दुर्घटना के बाद परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, छात्रों को बिना किसी आर्थिक चिंता के शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्र सुरक्षा बीमा योजना शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो छात्रों के सुरक्षित और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हरडुआ की बालिकाओं ने जीता उद्घाटन मैच

विकासखण्ड स्तरीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा के तहत हाई स्कूल परसबोड़ में हुई कबड्डी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| साजा

विकासखण्ड स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत कबड्डी 17 वर्ष बालक/बालिका खेल का आयोजन शासकीय हाई स्कूल परसबोड़ में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्जवलित कर एवं पूजा अर्चना कर किया गया।

संस्था के प्राचार्य के ईश्वर लाल साहू एवं पवन साहू प्रधान पाठक विकास खण्ड क्रीड़ा प्रभारी जवाहर कुर्रे, संस्था के वरिष्ट व्याख्याता अंजुलता गार्डिया, सबिता बिस्वास, सीमा राजपूत, कविता वर्मा, विष्णु धीवर, नोकेश्वर वर्मा, खेमलाल साहू एवं व्यायाम शिक्षकों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस खेल प्रतियोगिता में विकास खण्ड से लगभग 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्पर्धा में बालक-बालिका अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगे। प्रथम मैच केहका और हरडुवा बालिका के मध्य खेला गया, जिसमें हरडुआ बालिका की टीम विजयी रही। दूसरा मैच परसबोड़ एवं खैरझिटीकला के बीच खेला गया, जिसमें परसबोड़ की टीम विजयी रही। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आये व्यायाम शिक्षक वरुन सिंह राजपूत, वेद प्रकाश साहू, हर्ष यादव, राजेन्द्र साहू, ऋषभ सिंह राजपुत, ऐलाराम देवांगन , नोकेश्वर वर्मा, रूपेश कुमार सप्रे, झुलुराम रजक, जितेन्द्र साहू, गौतम साहू,अजय साहू, ईश्वर लाल साहू, खेमलाल साहू, बी उमाशंकर, गीतेश्वरी ताम्रकार ,अजय निर्मलकर, एम रवि राज, प्रभु साहू उपस्थित रहे।

शासकीय कन्या प्राथमिक शाला देवकर में बाल कैबिनेट का गठन

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बेमेतरा

शासकीय कन्या प्राथमिक शाला देवकर में बाल कैबिनेट का गठन किया गया।

इसके चयन के लिए प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाई गई। प्रत्येक पद के लिए उम्मीदवारों के नाम आमंत्रित किया गया तथा अधिक बच्चों के नाम आने पर मतदान की प्रणाली अपनाई गई। शिक्षकों के द्वारा अधिक मत प्राप्त करने वाले छात्राओं को पद प्रदान किया गया। जिसमें शाला नायिका के पद पर जानवी, उपशाला नायिका याचना पटेल, खेल और सांस्कृतिक प्रभारी चंचल, सहयोगी में सोनिया और कावेरी, अनुशासन प्रभारी डिलेश्वरी सहयोगी दीपा और भुनेश्वरी, स्वच्छता प्रभारी सुहानी सहयोगी में योगिता पूर्णिमा और यामिनी, शिक्षा मंत्री भूमिका और भावना तथा बाल बैंक संचालन प्रभारी यामिनी और शाइमा को साथ ही हर सप्ताह कक्षा संचालन हेतु इस सप्ताह के संचालन हेतु सभी बच्चों को प्रभार सौंपे गये।

समस्त पदाधिकारीयों का गुलाल और बैच लगाकर स्वागत किया गया। प्रधान पाठिका गिरिजा पटेल द्वारा बच्चों को बताया गया कि विद्यालय में बाल केबिनेट के गठन का हमारा उद्देश्य बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास, दायित्व बोध और सामूहिकता की भावना जागृत करना हैं। बाल केबिनेट के गठन से बच्चों में कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का उदय होगा। साथ ही हमारी शाला अनुशासित, सुंदर, सक्रिय एव व्यवस्थित नजर आयेगी। चुनाव पश्चात बच्चों को अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विद्यालय की शिक्षिका वीणा रावटे, श्वेता वर्मा, शिक्षक आशुतोष चौबे उपस्थित थे।

चेक बाउंस मामले में चंदन को 10 माह का सश्रम कारावास

देवरीबंगला। आदतन चेक बाउंस कराने वाले चंद्र प्रकाश साहू उर्फ चंदन को अंततः चंदन लग ही गया और 10 माह के सश्रम कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 4,52,000 उधार लिए जाने के बाद हजम कर जाने की नियत रखकर प्रार्थी को भुगतान नहीं कर लगातार घुमा रहा था। काफी दिनों तक परेशान हो जाने के बाद आखिर प्रार्थी थाने की शरण में पहुंचा। परंतु काफी मशक्कत के बाद न्यायालय पहुंचा और अंततः उन्हें न्याय मिला।न्यायालय ने प्रार्थी की पूरी राशि वापस करने का आदेश चंदन को दिया। चंदन जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए न्यायालय की कड़ी कार्रवाई ने संदेश दे दिया है कि ठगी करने का प्रयास न करें, चेक के मामले में चेक अनादृत न होने दें। मिली जानकारी के अनुसार चंद्रप्रकाश साहू उर्फ चंदन पिता दौलत राम साहू निवासी खपराभाट ने अपने परिवार के जीतेश कश्यप से 4,51,150 उधार लिया था। इसके बाद काफी समय बीत जाने पर जीतेश कश्यप ने चंद्रप्रकाश से अपनी रकम वापस मांगी।

डौंडीलोहारा पहुंचे उपमुख्यमंत्री शर्मा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

हरिभूमि न्यूज ▶▶| डौंडीलोहारा

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा के डौंडीलोहारा प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।

उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यकर्ताओं ने गजमाला से विजय शर्मा एवं जिला अध्यक्ष पवन साहू का स्वागत किया। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ मण्डल संगठन के संबंध में चर्चा करते हुए भेंट मुलाकात की गई। मण्डल अध्यक्ष रूपेश सिन्हा एवं कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष सौंदर्यीकरण की मांग की, जिस पर मंत्री श्री शर्मा ने हामी भरी। इस अवसर पर देवलाल ठाकुर, दिलीप शर्मा, रूपेश सिन्हा, मनीष झा, दारा सिंह भौसार्य, संदीप जैन,अजय चौहान,टोमन साहू महावीर साहू, जसराज शर्मा, धीरेंद्र टांक, पलाश गुप्ता, सुरेश देशमुख, डोमेंद्र देशमुख,लिलेन्द्र सिन्हा, माया ठाकुर,आरती संचेती, भुषण साहू, अशोक साहू ,राजू भंसाली, निरंजन पटौदी,शिव भुआर्य,पाल सिंह यादव,शिव मसिया, नीलकमल साहू,चांदमल जैन, सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भेंट मुलाकात कर वे जामड़ी पाटेश्वरधाम के लिए रवाना हुए।

आरटीई पोर्टल से चयनित बच्चों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दें

- संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

बालोद। जिले में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिनियम 2009 के समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में चन्द्रवाल ने विद्यालयों में आरटीई पोर्टल में लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश के अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत जिले में चल रहे अन्य सभी क्रियाकलापों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों के आरटीई पोर्टल के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

इसके अलावा उन्होंने आरटीई के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, गणवेश, लेखन सामग्री आदि की भी निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने जिला स्तरीय समिति की नियमित रूप से समीक्षा बैठक आयोजित कराने तथा जिले में इनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए पुख्ता उपाय करने के भी निर्देश दिए।

समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

निर्धारित समय पर पूर्ण करें सभी कार्य : शर्मा

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बेमेतरा

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कलेक्टोरेट के दिशा सभाकक्ष में जिले के कार्यों की समीक्षा करने समय सीमा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से शासकीय कार्यों के कामकाज की रिपोर्ट ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। और विकास कार्यों की प्रगति, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, और समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी, संयुक्त कलेक्टर द्वेय अंकिता गर्ग, टेकराम माहेश्वरी, सर्व एसडीएम, सर्व जनपद सीईओ, सर्व सीएमओ सहित जिला के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री शर्मा ने सभी अधिकारीयों को जनकल्याणकारी शासकीय कार्यों में गति बढ़ाने के शख्त निर्देश दिए, उन्होंने कार्यों में धीमी प्रगति को लेकर नाराजगी जताई। जिलाधीश ने कहा कि यह अंतिम चेतावनी है, सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण कर लें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने जिले में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने रामलला के दर्शन के दूसरे चरण की समीक्षा करते हुए व्यवस्थाओं की जांच की और संबंधित अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त किया। जिलाधीश ने पीएम किसान सम्मान निधि की जानकारी ली और जल्द से जल्द पात्र हितग्राहियों का आधार सीडिंग कार्य पूर्ण करने को कहा। उन्होंने सभी शिक्षकों को समय पर स्कूल आने और शैक्षणिक कार्य को गंभीरता से लेने को कहा। श्री शर्मा ने स्कूलों की स्थिति सुधारने और छात्रों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने को कहा।

मवेशियों को खुले में छोड़ा तो खैर नहीं

कलेक्टर ने रास्ते में बैठने वाले आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए गठित विशेष टीमों की गतिविधियों का मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि हाईवे से सभी पशुओं को हटाकर उनकी उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो नागरिक मवेशियों को आवारा छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने तथा जुर्माना वसूलने को कहा।

तेज आवाज में डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई

बैठक के दौरान प्रेशर हार्न, तेज ध्वनि वाले वाहनों में लगे साइलेंसर, तेज ध्वनि में बजने वाले डीजे, धार्मिक संस्थानों में लगे लाउडस्पीकर आदि के निर्धारित मात्रा से अधिक आवाज न हो। इसके लिए वाहनों को मोडीफाय करने वाले गैरेज तथा मैरिज पैलेस, डीजे संचालकों को भी नियम की जानकारी देने को कहा गया।

मानव उत्थान सेवा समिति ने एकत्रित की स्टेशनरी सामग्री

हरिभूमि न्यूज ▶▶| कुसुमकसा

- शासकीय विद्यालयों के जरूरतमंद बच्चों को की जाएगी वितरित

मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा मिशन एजुकेशन सेवा कार्य पूरे भारत सहित विश्व के कई देशों में विगत 6 वर्षों किया जा रहा है।

संस्था द्वारा स्टेशनरी सामग्री जैसे पेन कापी, पुस्तक काफी, रबर पेंसिल, सहित अन्य सामग्री इकट्ठा कर सरकारी स्कूलों में जरूरतमंद गरीब बच्चों को वितरित किया जाता है। इसी के तहत सोमवार को मानव उत्थान सेवा समिति जिला बालोद द्वारा कुसुमकसा में डोनेशन बॉक्स लगाया गया। इसमें संजय बैस जनपद सदस्य के आह्वान पर व्यापारी संघ के व्यापारियों एवं राम जानकी समिति के सदस्यों ने कुसुमकसा में स्टेशनरी दान किया। बच्चों के लिए स्टेशनरी सामग्री दान करने वालों में संजय बैस जपनद सदस्य एवं राम जानकी समिति, प्रकाश चंद कुचेरिया व्यापारी संघ अध्यक्ष, संतोष जैन आदि उपस्थित थे।